शार्ट स्टेपल काटन पर से निर्यात शुल्क को हटाने के लिए ज्ञापन

849. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को शार्ट स्टेपल काटन पर से निर्यात शुल्क हटाने के लिए गुजरात स्टेट कोआपोरेटिव काटन मार्केटिंग फेडेरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद से मई, 1979, में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगे रखी गई हैं,

(ग) इन मांगो के कब तक स्वीकार किए जाने की आशा है,

(घ) 24 5 मि0 मी0 और इससे अधिक लंबाई के स्टेपल वाली कपास और बंगाली देशी नामक किस्म को छोड़कर काटन की अन्य सभी किस्मो पर इस समय प्रति टन कितना निर्यात शुल्क लगा है,

(ङ) 31 मई, 1978 को तथा 31 मई, 1979 को गुजरात की विभिन्न किस्मो की काटन के क्या भाव थे, और

(च) क्या सरकार गुजरात की काटन पर वसूल किए जा रहे निर्यात शुल्क को वापिस लेंगी और यदि हां, तो कब तक और कैसे वापिस लेगी तथा यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) से (ग). 4 मई 1979 को वित्त मंत्रालय में प्राप्त 28-4-79 के एक ज्ञापन में गुजरात राज्य सहकारी सूत विपणन महासंघ लि0, अहमदाबाद ने सरकार से छोटे रेशे वाली रुई पर और खास तौर पर प्रमुख सहकारी विपणन महासंघ द्वारा निर्यात की जाने वाली रुई पर निर्यात शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन किया था। मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सरकार ने छोटे रेशे वाली रुई के एक वर्ग के रूप में निर्यात शुल्क से छूट देने के बारे में महासंघ के अनुरोध को मानने में असमर्थता ज़ाहिर की है, हालांकि कपास की कतिपय किस्मों के संबंध में तदर्थ आधार पर निर्यात शुल्क से छूट दी गई थी।

(घ) कपास पर (बंगाल देशी को छोड़कर) निर्यात शुल्क की वर्तमान दरें नीचे दी गयी हैं —

(रु० प्रति टन)

1.	निम्नलिखित किस्म की कपास	
	(क) आसाम/कोमिला रुई (ख) पीली बची खुची और ज्यादा रुई (अर्थात् तीसरे चयन और न काती जाने योग्य किस्म की रुई) (ग) बची खुची और अपशिष्ट रुई जो देश में व्यावहारिक इस्तेमाल की न हो।	550
2.	24 5 मिली मीटर और इससे अधिक की लम्बाई के रेशे वाली कपास	शून्य
3.	कपास की अन्य सभी किस्में (बंगाल देशी को छोड़कर)	1000

(ङ) गुजरात में उत्पन्न रुई के लिए निर्यात शुल्क की कोई अलग दर नहीं है।

(च) सरकार को छोटे रेशे वाली रुई पर वर्ग के रूप में निर्यात शुल्क हटाने का पर्याप्त औचित्य नहीं दिखाई देता। लेकिन, उन विशिष्ट मामलों में जिनमें यह पाया जाता है कि जिस मूल्य पर ऐसी कपास निर्यात की जा सकती है, वह लाभ कर नहीं है तो छूट देने के लिए मामले पर इसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई-केशोद-पोरबन्दर के लिए सुबह की दूसरी उड़ान

850 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस समय बम्बई-केशोद-पोरबन्दर के बीच केवल एक छोटी उड़ान आई0 सी0 137/138 ही है जिसके कारण कई सवारियों को सीट नहीं मिलती और उन्हें बहुत असुविधा होती है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुबह कोई दूसरी उड़ान चालू करने का है,

(ख) यदि हां, तो सुबह में दूसरी उड़ान कब तक चालू कर दी जाएगी,

(ग) यदि सरकार बम्बई-केशोद-पोरबन्दर के बीच दूसरी दैनिक उड़ान चलाने की स्थिति में नहीं है तो क्या सप्ताह में चार दिन दूसरी दैनिक उड़ान चालू कर सकती है, यदि हां तो कब तक, और

(घ) बम्बई राजकोट की उड़ान की भांति बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच सप्ताह में चार दिन दूसरी उड़ान का प्रारंभ कब तक कर दिया जायेगा और सरकार तथा इंडियन एयरलाइन्स को इसमें क्या कठिनाइयां हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). एक दैनिक एच एस-748 सेवा आई सी-137/138 केशोद और पोरबदर को बम्बई से जोड़ती है। विमानो की कमी के कारण फिलहाल बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच सेवाओं की संख्या में वृद्धि पर विचार कर सकना संभव नही।

Selection of Income-tax Inspectors

851. SHRI VASANT SATHE: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) the number of persons selected for the post of Income-tax Inspectors during 1977-78 and 1978-79, State-wise in general and Maharashtra State in particular;

(b) the additional number of Inspectors asked for by the Maharashtra Income-tax Commissioner and the action taken by the Government in this regard; and

(c) estimated number of posts of Income-tax Inspectors likely to be created?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE : (SHRI ZULFIQUARULLAH) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House;

(c) 500 posts of Income-tax Inspectors have been sanctioned for survey work. Out of these 500 posts, 75 have been allocated to Commissioner of Income-tax located in Maharashtra State

Sale of Flat by Shrimati Padma Desai

852. SHRI VASANT SATHE : Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have looked into Shrimati Padma Desai's (Prime Minister's daughter-in-law) Chitrakut flat sale deal at Bombay as promised during the last Session of Parliament ;

(b) if so, details of progress made in investigation and further action taken on the basis of findings; and

(c) what is the factual position in regard to the 12 points listed in the news story appearing in the news weekly 'Current' dated 26-5-79 page 1 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (c). The Hon'ble Member has presumbly in view the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 6322 answered on 6-4-1979 in the last Session of Lok Sabha Investigations in the matter are still in progress. Details of the investigations and the factual position in regard to the 12 points listed in the news weekly 'Current' cannot be divulged, as it may hamper the progress of the investigations.

Bombay as vegetable market for foreign countries

853 SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK :
SHRI G.M. BANATWALLA
SHRI CHIMANBHAI H. SHUKLA :
DR BIJY MONDAL :
SHRI BHANKER SINHJI VAGHELA :

Will the MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to promote Bombay as Vegetable market for Dubai and other European countries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which the proposal will be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (c). Export of vegetables is allowed only through Central and State Corporations and Marketing Federations. Maharashtra Agro Industries Development Corporation have been allowed to undertake export of vegetables from Bombay to all destinations within a ceiling of 300 tonnes per month subject to the condition that the quantity exported will not more than 50% of the additional production to the undertaken by the Maharashtra State Government. The State Government will be having contract cultivation of vegetables shortly for exports.

Liberalisation of seed capital scheme in IDBI

854. SHRI K. MALLANNA : Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER FOR FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that I.D.B.I. has liberalised the seed capital scheme recently;